O. T. Allowance to Ministerial Staff

1287. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any provision for payment of over-time allowance to the Ministerial staff;

(b) if so, why Ministerial staff are not paid over-time for working extra hours beyond rostered duty hours;

(c) whether there is a ban on creation of posts and recruitment of Ministerial staff;

(d) if so, why it is not lifted and Ministerial staff are not recruited in proportion to the staff recruited in other categories to cope with increased work-load;

(e) whether split duty allowance is granted to the Ministerial staff performing shift duty in work-shops by the Railway Board; and

(f) if so, why it was stopped and what decision Government have taken on this issue?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes But when booked to work on the day of their rest, they are required to be given compensatory day of rest.

(b) They are not normally booked to work overtime. However, when required to do special items of work or extra work justifying extra payment, the ministerial staff are generally paid honorarium for the additional work.

(c) While there is a ban on creation of new posts, there is no ban for recruitment to clerical categories to fill vacancies created due to normal attrition.

(d) The ban on the creation of new posts has been imposed on the Railways in pursuance of ban orders issued by the Ministry of Finance as a measure of economy and the Ministry of Railways can not lift it unilaterally.

(e) No.

(f) The ministerial staff who avail of rest interval for their own convenience and not in the administrative interest are not eligible for the benefit of split shift duty. The concession was, therefore, not extended to these staff.

वैगनों से माल न उतारना

1288. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि व्यापारियों द्वारा वैगनों के समय पर माल न उतारने के कारण, वैगनों की भारी कमी हो गई है और रेलवे गोदामों पर वैगनों को खड़ा करने में भी भारी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) रेलें कुछ स्थानों पर परेषितियों द्वारा उतराई के लिए अनुमत छूट समय के भीतर माल डिब्बों को खाली न किये जाने के बारे में चिंतित है। यह भी माल डिब्बों के अपेक्षाकृत अधिक फेरों और परिणामस्वरूप उनकी उपलब्धता कम होने का एक कारण है। यद्यपि केवल यह ही माल डिब्बों की भारी कमी होने का कारण नहीं है तथापि इससे मौके-बे-मौके कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

(ख) माल डिब्बों को शीघ्रतापूर्वक खाली करके और इस प्रकार माल डिब्बों की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सितम्बर, 1979 से विलम्ब शुल्क दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि ।

(2) सितम्बर, 1979 से 60 पैसे प्रति टन प्रति घंटे की दण्डात्मक विलम्ब शुल्क दरों को बढ़ाकर 1.50 रु. प्रति टन प्रति घंटा करना ।

(3) स्वयं रेलों द्वारा माल डिब्बों से माल उतारना और उसके लिए सुपुर्दगी के समय पार्टियों से प्रभार लेना ।

(4) माल डिब्बों को शीघ्र खाली कराने और उतारे गये परेषणों को हटाने के लिए व्यापारियों और स्थानीय वाणिज्य मंडलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ निकट सम्पर्क ।

(5) विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क की उच्चतर दरें लगाने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों को निम्नतर कोटि से उच्चतर कोटि में पुन: वर्गीकृत करने के लिए रेलों को प्राधिकृत करना ।

(6) प्रमुख माल गोदामों और स्टेशनों पर रविवार के दिन के लिए भी स्थान शुल्क लागू करना ।

(7) कतिपय महत्वपूर्ण स्टेशनों को "अधिसूचित स्टेशन" घोषित करना जहां रेलों को उन स्टेशनों पर उठाये जाने की प्रतीक्षा में पड़ी हुई और परिवहन अवधि के समाप्त होने के सात दिन के अन्दर सुपुर्दगी न ली गयी आवश्यक वस्तुओं के निपटान की शक्तियां प्राप्त हैं। सम्प्रति, भारतीय रेलों पर 100 से अधिक स्टेशनों को "अधिसूचित स्टेशन" घोषित किया जा चुका है।

Lalitpur-Satna Railway Line

1289. SHRI ARVIND NETAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the feasibility survey for Lalitpur-Satna Railway Line has been included in the current years' Railway budget;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). A preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for the construction of a 455 kms. long new line from Lalitpur to Singrauli via Khajuraho, Satna and Rewa was taken on hand in December 1978 and is expected to be completed by the end of March, 1981.

Introduction of Train on Khazipet-Balharshah Section

1290. SHRI G. NARSINMHA REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the South Central Railway has neglected to provide convenient train facility for Khazipet-Balharshah section, which is important industrial belt in Andhra Pradesh, to go to Hyderabad; and

(b) if so, whether Government propose to issue necessary instructions to introduce the train immediately?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). At present 2 pairs of trains viz. 21/22 New Delhi-Hyderabad Express and 335/336 Hyderabad-Nagpur Passenger connect Ballarshah-Khazipet with Hyderabad. In addition passengers can also travel by availing of the connecting services with change-over at Khazipet.

Introduction of an additional train on this route is not operationally feasible due to saturated line capacity on sections enroute and inadequate terminal facilities at Hyderabad.

दिलदार नगर से गोरखपुर तक की लाइन

1291. **श्री जेनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे में मुगलसराय पटना सेक्शन में दिलदार नगर स्टेशन से गाजीपुर, मउनाथ भंजन, दोहरीघाट होते हुए गोरखपुर तक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव मिला है ;